संख्या-24/2023/618/23-2-23-06(सा)/23

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक:23 अगस्त,2023

विषय:-जनपद महराजगंज में सौनौली-नौतनवा-गोरखपुर मार्ग (एन0एच0-24(29ई) मार्ग के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउद्देशीय हब के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-62/पी0जे011/15पी0जे0/23, दिनांक 15.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में 01 प्रतिशत निबन्धन शुल्क का प्राविधान करते हुए धनराशि रू0 3947.66 लाख का पुनरीक्षित आगणन/ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-02/2023/90/23-2-23/001-06(सा0)/23, दिनांक 07.03.2023, शासनादेश संख्या-4/2023/90(1)/23-2-23-06(सा0)/23, दिनांक 16.03.2023 (शुद्धि पत्र) एवं शासनादेश संख्या-7/2023/425/23-2-23/001-06(सा0)/23, दिनांक 30.03.2023 द्वारा विषयगत कार्य हेतु कुल धनराशि रू0 39,09,01,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि रू0 39,09,00,250.00 निर्गत की गयी थी।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य के लिए 01 प्रतिशत निबन्धन शुल्क का प्राविधान करते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 3947.66 लाख (रूपये उनतालीस करोड़ सैंतालीस लाख छाछठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिये किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5)- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6)- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7)- लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01 सितम्बर 2018 के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8)- लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उक्त पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054045571352 अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउददेशीय हब का निर्माण मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-464-एक्स-2023-24 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

संख्या-24/2023/618(1)/23-2-23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- संबंधित मण्डलायुक्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महराजगंज।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वेब अधिकारी प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8 उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।